कानपुर, बुधवार, 29 अप्रैल, 2026
वर्ष: 03, अंक: 106, पृष्ठ: 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड खबरों के लिए 2.25% टैक्स का प्रस्ताव...>Pg12

खाड़ेपुर के 200-300 घरों में पेयजल संकट...>Pg03

मूल्य: 2 ₹

गंगा एक्सप्रेस-वे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन, हरिद्वार से जुड़ाव का बड़ा ऐलान

उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा 'विकास पथ'

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

हरदोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरदोई से उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का भव्य उद्घाटन कर प्रदेश को एक ऐतिहासिक सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने एक्सप्रेस-वे को हरिद्वार से जोड़ने का बड़ा ऐलान करते हुए इसे राष्ट्रीय और धार्मिक दृष्टि से और अधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल विकास का प्रतीक है, बल्कि रोजगार, उद्योग और पर्यटन के नए द्वार भी खोलेगी।

उद्घाटन कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेस-वे किनारे पौधारोपण किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ दूरी तक पैदल चलकर परियोजना का निरीक्षण भी किया। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है और 12 जिलों से होकर गुजरता है। इसके शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज की यात्रा अब मात्र 6 घंटे में पूरी हो सकेगी, जो पहले 11-12 घंटे में होती थी।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विकास के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जनता से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में अब विकास की राजनीति ही आगे बढ़ेगी। गंगा एक्सप्रेस-वे आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें जगह-जगह पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर बनाए गए हैं, जहां यात्रियों को ठहरने, भोजन और चिकित्सा की सुविधाएं मिलेंगी। विशेष रूप से ट्रॉमा सेंटर और फूड कोर्ट इसकी खास पहचान

➪ **594 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस-वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है और 12 जिलों से होकर गुजरत**

बनेंगे। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रंबल स्ट्रिप्स (उभरी पट्टियां) बनाई गई हैं, जिनसे वाहन के गुजरने पर कंपन महसूस होता है और चालक सतर्क हो जाता है। इस एक्सप्रेस-वे की एक और बड़ी खासियत शाहजहांपुर के जलालाबाद के पास बनाई गई 3.5 किलोमीटर लंबी एयरस्ट्रिप है, जहां एयरफोर्स के फाइटर जेट्स नाइट लैंडिंग कर सकेंगे। यह देश की पहली ऐसी एयरस्ट्रिप है, जो रात में भी ऑपरेशन के लिए सक्षम है। हर 75 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप की व्यवस्था की गई है, जिसे भारत पेट्रोलियम संचालित करेगा। लगभग 37,350 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना

कब क्या हुआ

- **18 दिसंबर 2021:** शिलान्यास
- **2022-2025:** निर्माण कार्य
- **2026:** उद्घाटन और संचालन शुरू

आर्थिक प्रभाव

- औद्योगिक निवेश में वृद्धि
- कृषि उत्पादों की तेज ढुलाई
- रोजगार के नए अवसर
- लॉजिस्टिक्स लागत में कमी

को पूरा होने में करीब 5 साल लगे। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था।

गंगा एक्सप्रेस-वे के शुरू होने से प्रदेश के औद्योगिक, कृषि और पर्यटन क्षेत्रों को नई गति मिलने की उम्मीद है। यह न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि निवेश को भी आकर्षित करेगा और उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

- 594 किमी लंबा यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे
- मेरठ से प्रयागराज की दूरी घटकर 6 घंटे
- 12 जिलों को सीधे जोड़ेगा
- हरिद्वार से जोड़ने की घोषणा
- 3.5 किमी लंबी नाइट लैंडिंग एयरस्ट्रिप
- 37,350 करोड़ रुपये की लागत
- हर 75 किमी पर पेट्रोल पंप और सुविधाएं

परियोजना की खासियतें

- पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर
- ट्रॉमा सेंटर और फूड कोर्ट
- रंबल स्ट्रिप्स से सुरक्षा
- हाईटेक सड़क डिजाइन

रक्षा के लिए अहम

- एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप
- नाइट ऑपरेशन की सुविधा
- रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण

ओवरटेक की कोशिश बनी हादसे की वजह, बोलेरो दो ट्रकों के बीच फंसी

मुंडन समारोह में जा रहे परिवार के 6 लोगों की मौत

उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

उन्नाव। उन्नाव-रायबरेली मार्ग पर बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि तीन महिलाओं के शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए और एक महिला का सिर धड़ से अलग होकर करीब चार फीट दूर जा गिरा।

घटना बिहार थाना क्षेत्र के कीरतपुर गांव के पास सुमेरपुल के नजदीक सुबह करीब 10:30 बजे हुई। जानकारी के

➪ **मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक, 2-2 लाख रुपये की राहत राशि का ऐलान**

मुताबिक, मौरावां थाना क्षेत्र के सूरज सिंह अपने तीन वर्षीय बेटे शुभ का मुंडन संस्कार कराने के लिए परिवार के 10 सदस्यों के साथ बोलेरो से बक्सर गांव स्थित चंडीदेवी मंदिर जा रहे थे।

रास्ते में तेज रफ्तार बोलेरो चालक ने आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी वाहन ट्रक से टकरा गया। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने भी बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी। दो ट्रकों के बीच फंसने से बोलेरो बुरी तरह पिचक गई और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब

छह फीट गहरी खाई में जा गिरी। पीछे वाला ट्रक भी संतुलन खोकर खाई में पलट गया और बोलेरो को कुचलते हुए आगे जा गिरा।

हादसे में बोलेरो सवार लोग अंदर ही फंस गए। तीन महिलाओं के शरीर कई टुकड़ों में बंट गए, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने किसी तरह घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान ड्राइवर रामधनी यादव ने दम तोड़ दिया। मृतकों में गीता सिंह, ज्योति, सुनीता सिंह, अर्चना बाजपेयी, वितान और चालक रामधनी यादव शामिल हैं। यह हादसा एक खुशियों भरे मौके को मातम में बदल गया, जहां एक मासूम के मुंडन संस्कार की खुशी पलभर में शोक में तब्दील हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सीओ बीघापुर मधुपनाथ मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा ओवरटेक के दौरान हुआ प्रतीत होता है। मामले की जांच की जा रही है।

विधायक अमिताभ बाजपेई के विरोध का असर, नानाराव पार्क का तरणताल शुरू

तरणताल के साथ-साथ पार्क में स्थित ओपन जिम की हालत अब भी खराब बनी हुई है

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नाना राव पार्क स्थित लंबे समय से बंद पड़ा तरणताल आखिरकार शुरू हो गया। क्षेत्रीय विधायक अमिताभ बाजपेई के विरोध और लगातार दबाव के बाद प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी और स्विमिंग पूल को आम जनता के लिए खोल दिया गया।गौरतलब है कि हर वर्ष मार्च माह में होली से पहले शुरू होने वाला यह तरणताल इस बार अप्रैल के अंत तक भी बंद पड़ा था, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी थी। विधायक अमिताभ बाजपेई ने कई बार मौके का निरीक्षण कर अधिकारियों को चेतावनी दी थी और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे।

विरोध तेज होने के बाद प्रशासन हरकत व्यवस्थाएं पूरी कर तरणताल को चालू कराया गया। इसके शुरू होने से युवाओं और तैराकी के शौकीनों में खुशी की लहर है।हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि ओपन जिम की हालत अब भी खराब बनी हुई है। जिम की कई मशीनें खराब हैं और झूले टूटे पड़े हैं, जिन पर भी जल्द ध्यान देने की मांग उठ रही है।लोगों ने चेतावनी नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल तरणताल के शुरू होने से क्षेत्रीय जनता को बड़ी राहत मिली है।इस दौरान हरी ओम पांडे, चंकी गुप्ता, रजत बाजपेई, मो. सारिया, अनवर अली, विकास गुप्ता, सौरभ गुप्ता, सुरभित जायसवाल, दुर्गेश चक, सचिन यादव, आकाश यादव, प्रदीप सिंह, राजू खान, हर्ष नागवंशी, संस्कार खरे सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

एक दवा, दो बड़ी बीमारियों पर वार: कानपुर मेडिकल कॉलेज की रिसर्च ने बदली इलाज की दिशा

'सेमाग्लूटाइड' के ट्रायल में 20% तक वजन घटा, ब्लड शुगर भी नियंत्रित, मरीजों की इंसुलिन पर निर्भरता घटी

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। बढ़ते डायबिटीज और मोटापे के संकट के बीच कानपुर से एक उम्मीद भरी खबर सामने आई है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने एक ऐसी दवा पर सफल शोध किया है, जो एक साथ दो बड़ी बीमारियों डायबिटीज और मोटापे पर असरदार साबित हो रही है। 'सेमाग्लूटाइड' नामक इस दवा के ट्रायल के नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में इस दवा का परीक्षण करीब 313 मरीजों पर किया गया। शोध के दौरान सामने आया कि दवा लेने वाले मरीजों के वजन में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई। यही नहीं, उनके ब्लड शुगर लेवल में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला, जो डायबिटीज मरीजों के लिए सबसे बड़ी राहत है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस दवा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर में भूख को नियंत्रित करने के साथ-साथ इंसुलिन के प्रभाव को बेहतर बनाती है।

इससे न केवल वजन घटता है, बल्कि शरीर में शुगर का संतुलन भी बनाए रखना आसान हो जाता है। ट्रायल के दौरान कई मरीजों में इंसुलिन और अन्य दवाओं की जरूरत भी कम हो गई, जो लंबे समय से इलाज करा रहे मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात है।

इस शोध में देशभर के 17 प्रमुख सेंटर शामिल थे, जिनमें कानपुर का योगदान खास रहा। यहां के परिणाम इतने प्रभावी रहे कि विशेषज्ञ इसे हेल्थ सेक्टर में एक 'गेम चेंजर' मान रहे हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि अगर यह दवा व्यापक स्तर पर उपलब्ध होती है, तो डायबिटीज और मोटापे से जूझ रहे करोड़ों मरीजों के इलाज में बड़ा बदलाव आ सकता है।

फिलहाल, इस दवा को लेकर आगे और अध्ययन तथा दीर्घकालिक प्रभावों पर शोध जारी है, लेकिन शुरुआती नतीजों ने उम्मीदों को नई उड़ान दे दी है। चिकित्सा जगत में इसे एक संभावित क्रांति के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में इलाज की परिभाषा बदल सकती है।

काकादेव में केडीए का बुलडोजर एक्शन अवैध हॉस्टल व दुकानें जमींदोज

» 350 वर्ग मीटर में बना अवैध कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स ध्वस्त, भारी पुलिस बल रहा तैनात

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण (च्छ) ने मंगलवार को काकादेव क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रवर्तन जोन-2बी के अंतर्गत ब्लाक-एन स्थित भूखण्ड संख्या-86 पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

प्राधिकरण के अनुसार, संबंधित भूखण्ड पर लगभग 350 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना अनुमति के चार व्यवसायिक दुकानों के साथ 17 कमरों का हॉस्टल तैयार कर लिया गया था। लंबे समय से नोटिस और चेतावनी के बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद केडीए ने सख्त रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।

यह पूरी कार्रवाई विशेष कार्याधिकारी सत् शुक्ला के नेतृत्व में संपन्न हुई। मौके पर अवर अभियंता कैलाश सिंह, प्रवर्तन दल, सुरक्षा कर्मियों के साथ तीन जेसीबी मशीनें तैनात रहीं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही। केडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नवनियुक्त सीडीओ अभिनव जैन का कर्मचारियों ने किया भव्य स्वागत

» समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिया

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नव नियुक्त मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन (आईएएस) का बुधवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री व जिला अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने सीडीओ को पुष्पगुच्छ भेंट कर तथा अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया।शिष्टाचार भेंट के दौरान जिला मंत्री इंजीनियर कोमल सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी को परिषद के पदाधिकारियों से परिचित कराया। इस मौके पर मण्डलीय मंत्री अजय कुमार द्विवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणधीर सिंह यादव, उपाध्यक्ष योगेन्द्र कुमार सिंह, शरद मिश्रा, दिनेश यादव, क्रिस्टी सिंह, इंजीनियर शिव करण सिंह और गगनदीप सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जैन ने स्वागत के लिए परिषद का आभार जताते हुए भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय से ही जनहित के कार्य प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में परिषद के पदाधिकारियों ने प्रशासन के साथ सकारात्मक सहयोग बनाए रखने का भरोसा जताया।

खाड़ेपुर में 2 महीने से गंदा पानी 200-300 घरों में पेयजल संकट

कॉलोनी में बीते लगभग 2 महीने से गंदे पानी की आपूर्ति का आरोप

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम के वार्ड 21 खाड़ेपुर के अंतर्गत खाड़ेपुर कॉलोनी में बीते लगभग 2 महीने से गंदे पानी की आपूर्ति ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात यह हैं कि करीब 200 से 300 घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है और लोग मजबूरी में उसी पानी का उपयोग करने को विवश हैं।

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जल संस्थान के अधिकारियों से कई बार शिकायत करने और फोन करने के बावजूद अब तक कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। समस्या लगातार बनी रहने से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

मंगलवार सुबह (28/04/2026) कॉलोनी के लोगों ने पूर्व पार्षद मधु मिश्रा और संदीप मिश्रा को मौके पर बुलाकर स्थिति से अवगत कराया। लोगों ने गंदे पानी को बोतलों में भरकर दिखाया और बताया कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

जनस्वास्थ्य पर खतरा

विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक दूषित पानी के उपयोग से जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, ऐसे में समय रहते सुधार जरूरी है। क्षेत्रवासियों ने जल संस्थान से तत्काल शुद्ध पानी की आपूर्ति बहाल करने, पाइपलाइन की जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व पार्षद संदीप मिश्रा ने बताया की जलकल के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है जल्दी पानी का इंतजाम होगा.

समस्या से जूझ रहे

सुरेन्द्र मिश्रा , अजय तिवारी, अनूप बाजपेई, रागिनी श्रीवास्तव , बीरेंद्र साहू , संजीव द्विवेदी, सहित देवेश तिवारी, मिथुन गुप्ता, योगेंद्र सिंह, ब्रजेश सचान, ओम प्रकाश, कामता, अतर सिंह यादव आदि ने समस्या को गंभीर बताया है।

स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

नजूल जमीन घोटाले पर सख्त रुख, सीएम ने मांगी पूरी रिपोर्ट

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। जिले में नजूल भूमि की अवैध खरीद-बिक्री के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने नजूल संपत्तियों के ब्योरे के साथ हाल के वर्षों में हुई रजिस्ट्री, उपयोग और स्वामित्व से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। खासतौर पर उन मामलों पर फोकस किया गया है, जहां सरकारी जमीन को नियमों के विपरीत बेचा या कब्जाया गया।

सिविल लाइंस के ग्वालटोली शूटरगंज इलाके में स्थित नजूल भूमि, जहां 42 वर्षों से सीबीसीआईडी कार्यालय संचालित था, उसे 24.77 करोड़ रुपये में निजी कंपनी को बेचने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। इस प्रकरण में कई नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जिले में बीते

➪ सीबीसीआईडी दफ्तर वाली जमीन की बिक्री ने बढ़ाई गंभीरता

एक वर्ष में नजूल जमीन से जुड़े कम से कम तीन बड़े मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें करीब 206 करोड़ रुपये की सरकारी संपत्तियों के अवैध सौदों के आरोप हैं। कई स्थानों पर बिना अनुमति बैनामे और निर्माण कार्य तक कराए जाने की बात सामने आई है।

मुख्यमंत्री स्तर से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद प्रशासनिक अमले में हलचल तेज हो गई है और विभिन्न विभागों से सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। अधिकारियों को आशंका है कि जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, साथ ही किसी संगठित गिरोह या मिलीभगत की भी पड़ताल की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नजूल भूमि सरकारी संपत्ति है और इसके अवैध हस्तांतरण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कानपुर को मिलेगी 'उड़ान' की नई पहचान पायलट ट्रेनिंग सेंटर को हरी झंडी

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। शहर को जल्द ही विमानन क्षेत्र में नई पहचान मिलने जा रही है। यहां अत्याधुनिक पायलट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। करीब 50 एकड़ जमीन के लिए रास्ता साफ हो चुका है और परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है। यह केंद्र फ्रांस के सहयोग से विकसित किया जाएगा, जहां कमर्शियल उड़ानों के लिए पेशेवर पायलट तैयार किए जाएंगे।

इस परियोजना के तहत युवाओं को केवल पायलट प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि एयरोनॉटिक्स, रक्षा और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भी उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। इससे

➪ फ्रांस के सहयोग से बनेगा अत्याधुनिक केंद्र, युवाओं को मिलेगा वैश्विक स्तर का प्रशिक्षण

स्थानीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ग्रीन बेल्ट श्रेणी हटाकर भूमि उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव पास किया गया है। अब अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव उड्डयन मंत्रालय और राज्य सरकार को भेजा गया है।

चकेरी एयरपोर्ट क्षेत्र के विस्तार के साथ ही जमीन आवंटन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

इसी परियोजना के अंतर्गत भारत-फ्रांस साझेदारी में एक नेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत विकसित होगा और युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल से लैस करेगा। इस पहल से कानपुर न केवल औद्योगिक बल्कि विमानन प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण हब के रूप में उभरने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

रूरा तिराहे पर भीषण सड़क हादसा

मामा-भांजी की मौत, पांच घायल

तेज रफ्तार ईको कार और ऑटो के बीच आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जनपद के शिवली थाना क्षेत्र अंतर्गत रूरा तिराहे पर मंगलवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। तेज रफ्तार ईको कार और ऑटो के बीच आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में ऑटो सवार मासूम भांजी और उसके मामा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते भारी भीड़ जुट गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ईको कार तेज रफ्तार में रसूलाबाद की ओर जा रही थी। इसी दौरान रूरा तिराहे पर शिवली से रसूलाबाद की ओर जा रहे ऑटो से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे में ऑटो सवार 4 वर्षीय मासूम श्रृष्टि की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बिरहुन रसूलाबाद निवासी 28 वर्षीय गोलू ने हायर सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

घटना में गणेशपुर बन्नापुर निवासी संजय, उनकी पत्नी सोनी (30 वर्ष), पुत्री मोहिनी (10 वर्ष), ऑटो चालक शाहरुख खान (27 वर्ष), कल्याणपुर कानपुर नगर निवासी रीता कटियार तथा ईको कार सवार औरैया जनपद के एरवाकटरा निवासी रामबाबू तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार में विवेक शुक्ला की पत्नी सीमा और उमा देवी भी सवार थीं, जो दवा लेने कानपुर जा रही थीं।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को शिवली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है।

हादसे के बाद ईको कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश भी देखा गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि फरार चालक की जल्द पहचान की जा सके।

मृतकों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन मौके पर पहुंच गए, जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल था। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि घायलों को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। फरार चालक की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है और तहरीर मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा व्यवस्था पर सख्ती बिना पंजीकरण कोचिंग और अमान्य स्कूल होंगे बंद

» डीआईओएस का कड़ा आदेश, 3 साल पूरे होने पर नवीनीकरण जरूरी, औचक निरीक्षण के लिए टीमें गठित

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिले में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) बृज भूषण चौधरी ने सभी कोचिंग सेंटर और विद्यालय संचालकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण या नवीनीकरण के संचालित हो रहे संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीआईओएस के अनुसार जिन कोचिंग सेंटरों का तीन वर्ष का पंजीकरण कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके लिए नवीनीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने ऐसे संस्थानों को अंतिम अवसर देते हुए निर्देश दिया है कि वे शीघ्र अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें। नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

इसके साथ ही प्रशासन ने बिना सरकारी मान्यता के संचालित हो रहे विद्यालयों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया है।

ऐसे सभी अमान्य स्कूलों को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि औचक निरीक्षण के दौरान यदि कोई संस्थान बिना वैध दस्तावेजों के चलता हुआ पाया गया, तो उसके संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

अवैध शिक्षा संस्थानों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें जिले के विभिन्न ब्लॉकों और कस्बों में कभी भी निरीक्षण कर सकती हैं। डीआईओएस ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल मान्यता प्राप्त और पंजीकृत संस्थानों में ही कराएं, ताकि उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार का जोखिम न हो।

कानपुर देहात कलेक्ट्रेट में बड़ा फेरबदल, तीन कर्मचारियों के बदले गए पटल

डीएम के आदेश पर तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां, रसूलाबाद से कर्मचारी मुख्यालय तलब

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। 28 अप्रैल 2026 को जारी आदेश के तहत पटल सहायकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए तीन कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

जारी आदेश के अनुसार राजस्व अभिलेखपाल नीरज मिश्र को उनके मूल पद के साथ जिला भूमि सुधार लिपिक (डीएलआरसी), स्टाम्प लिपिक पटल और अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय के वाचक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वहीं, उर्दू अनुवादक मो. शफीक सिद्दीकी को उनके वर्तमान कार्य के साथ एसीआरए (दैवीय आपदा) अनुभाग के कार्यों का दायित्व सौंपा गया है।

इसके अलावा तहसील रसूलाबाद में तैनात कनिष्ठ सहायक अक्षय मिश्रा को जिला भूमि सुधार लिपिक (डीएलआरसी) अनुभाग में टंकण कार्य के लिए संबद्ध किया गया है।

जिलाधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह सभी बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना किसी देरी के अपने नए पटल पर कार्यभार ग्रहण करें। साथ ही, रसूलाबाद तहसील से संबद्ध किए गए कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर कलेक्ट्रेट मुख्यालय भेजने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इस फेरबदल से कार्यों में तेजी आएगी और शासकीय कामकाज अधिक सुव्यवस्थित तरीके से संपादित हो सकेगा।

सम्पादकीय

मिले नए जिले मगर अहम मुद्दे अभी बाकी

जम्मू-कश्मीर से अलग होकर नया केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में जनाकांक्षाओं का जो उफान उठा है, केंद्र सरकार उसकी पूर्ति की दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। बीते साल राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर स्थानीय संगठन आंदोलित नजर आए थे। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के क्षेत्र के दौरे से पूर्व लद्दाख को पांच नये जिले मिले हैं। लेह और कारगिल के बाद- दो जिलों से बढ़कर सात जिलों तक का यह विस्तार इस पर्वतीय अंचल में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निश्चित रूप से इस विशाल भू-भाग वाले, लेकिन कम आबादी वाले क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए इस कदम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। दरअसल, लद्दाख के नुब्रा, जांस्कर और चांगथांग जैसे दूरदराज के इलाकों में बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच बनाने में स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यह बाधा सिर्फ भौगोलिक ही नहीं थी, बर्फीले दिनों में स्थिति और अधिक कष्टकारी हो जाती है। इसमें दो राय नहीं कि किसी भी क्षेत्र में छोटी प्रशासनिक इकाइयां अधिकारियों को जनता के करीब ला सकती हैं। खासकर लद्दाख जैसे जटिल भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में तो यह और भी जरूरी हो जाता है। निस्संदेह, छोटी प्रशासनिक इकाइयों के चलते सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तुरंत क्रियान्वयन को सुगम बनाने में मदद मिल सकती है।

सही मायनों में उपायुक्तों और पुलिस प्रमुखों की त्वरित नियुक्ति, बिना किसी देरी के सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक उत्साहजनक संकेत कहा जा सकता है। हालांकि, स्थानीय जनप्रतिनिधि संगठन नये जिले बनाने से संतुष्ट होते शायद ही नजर आएं। दरअसल, लद्दाख की चुनौतियां महज नौकरशाही तक ही सीमित नहीं कही जा सकती हैं। सही मायनों में ये राजनीतिक, आर्थिक व पर्यावरणीय भी हैं। वे जनाकांक्षाएं भी इसमें शामिल हैं जो लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद ऊंचे स्तर पर रही हैं।यहां उल्लेखनीय है कि लेह की अस्मिता की रक्षा के लिये आंदोलन चलाने वाले संगठन, मसलन कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन समेत कई स्थानीय समूह, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने और लेह-लद्दाख की संस्कृति की रक्षा के लिये इसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग करते रहे हैं। दरअसल, वे इसके लिये संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू करने का आग्रह करते हैं। वे विगत में हुई विभिन्न बैठकों को क्षेत्र के लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान के लिये अपर्याप्त बताते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पर्यावरणविद् व शिक्षाविद् सोनम वांगचुक, जिन्हें गत माह केंद्र सरकार ने लगभग छह माह की हिरासत के बाद रिहा किया था, ने भी शाह की यात्रा के दौरान एक रचनात्मक संवाद की जरूरत पर बल दिया है। वैसे राजग के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार गाहे-बगाहे लद्दाख के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती रही है। हालांकि, एक तथ्य यह भी है कि अभी तक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर उसका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। बहरहाल, क्षेत्र में पर्यटन नियमों में ढील और रोजगार के अवसरों को विस्तार देना जैसे सुधार, लद्दाख की आर्थिकी को गति देने का सार्थक प्रयास जरूर कहा जा सकता है। यह भी एक हकीकत है कि नवीनतम प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर जो आशावाद है, वह तभी सार्थक साबित होगा, जब इससे समावेशी विकास, बेहतर शासन और उचित राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो पायेगी। वहीं दूसरी ओर सरकार को इस व्यापक परिप्रेक्ष्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

भारत में एआई और सेमीकंडक्टर सेक्टर का असली इम्तिहान शेष

डॉ. नवीन कुमार

देशभर के विश्वविद्यालयों में आजकल एक होड़-सी मची है द्य एआई और सेमीकंडक्टर पर सेमिनार, वर्कशॉप और ज्यादा से ज्यादा एमओयू । हर संस्थान चाहता है कि उसका नाम इस नई तकनीकी क्रांति से जुड़े और उनके संस्थान का भी इस अभियान में सक्रिय योगदान हो। सरकार की तरफ से भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के रूप में एक बड़ी पहल हुई है, फैब लगाने की बात हो रही है, निवेश आ रहा है। यह सब देखकर मन में उम्मीद जगती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहे हैं ?

हकीकत यह है कि हमारी अधिकतर शिक्षण संस्थान एआई के सॉफ्टवेयर पक्ष पर तो खूब ध्यान दे रही हैं, लेकिन उसके नीचे जो हार्डवेयर की नींव है, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रही हैं। देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों से लेकर छोटे कॉलेजों तक में, छह-छह महीने के जेनरेटिव एआई में सर्टिफिकेट कोर्स की बाढ़ आई हुई है। ये कोर्स विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि विदेशी चिप पर बने, विदेशी कंपनियों के टूल को कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन यह नहीं सिखाते कि वह चिप बनती कैसे है, उसकी आर्किटेक्चर क्या होती है, उसका डिजाइन फ्लो क्या होता है। असली सेमीकंडक्टर संप्रभुता तब आएगी जब हम चिप के उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनेंगे।

विडंबना यह है कि इसका जवाब हमें कहीं बाहर से नहीं लाना। वह हमारे पास पहले से मौजूद है, बस हमने उसे देखना बंद कर दिया है। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक्स के बीएससी और एमएससी पाठ्यक्रमों में हर साल हजारों विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं। ये विद्यार्थी सेमीकंडक्टर फिजिक्स, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और डिवाइस की गहरी समझ रखते हैं। जो व्यक्ति तीन साल तक पीएन जंक्शन, मॉसफेट और ओपैम्प का व्यवहार पढ़ता है, वह किसी भी सॉफ्टवेयर बूटकैंप के स्नातक से कहीं ज्यादा चिप डिजाइन के करीब है।

लेकिन, नौकरी बाजार की सॉफ्टवेयर-फर्स्ट मानसिकता इन्हें आईटी सर्विस कंपनियों में धकेल देती है। उनकी हार्डवेयर की समझ जो कुछ निर्माण कर सकती थी, धीरे धीरे दूसरे के निर्माण के प्रयोग करने तक में सीमित हो जाती है।

तो रास्ता क्या है? जरूरत नई पाइपलाइन बनाने की नहीं, बल्कि जो पहले से है उसे सँवारने की है। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के दो साल के पाठ्यक्रम में टीसीएडी सिमुलेशन, स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस, फिजिकल वेरिफिकेशन और मुफ्त ईडीए टूल्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से शामिल होनी चाहिए। फ़ाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट को महज एक औपचारिकता नहीं रहने देना चाहिए – उसे एक वास्तविक चिप डिजाइन अनुभव में बदला जाए जिसमें विद्यार्थी एक कार्यात्मक ब्लॉक तैयार करे और उसे एमपीडब्ल्यू रन के जरिए जमा करे। अगर देश के केवल कुछ एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भी यह कदम उठाएँ, तो पाँच साल में भारत के पास चिप डिजाइनरों की एक पूरी पीढ़ी तैयार हो सकती है।

नीति-निर्माताओं को भी सफलता के पैमाने बदलने होंगे। संगोष्ठियों की संख्या, नामांकन के आँकड़े और एमओयू की फेहरिस्त – ये किसी संस्थान की तकनीकी क्षमता का प्रमाण नहीं हैं। असली प्रगति तब दिखेगी जब पेटेंट होंगे, आईपी कोर होंगे, एमपीडब्ल्यू सबमिशन होंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत जो नई उत्पादन सुविधाएँ बन रही हैं, उनके बजट का एक निश्चित हिस्सा उद्योग-अकादमिक शोध सहयोग पर अनिवार्य रूप से खर्च होना चाहिए – ताकि विश्वविद्यालय असली नवाचार के केंद्र बनें। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि शिक्षा सुधार अकेले आधी लड़ाई ही जीत सकता है। बाकी आधी लड़ाई बिना उद्योग जगत के सहयोग के नहीं लड़ी जा सकती । जब तक कंपनियाँ भर्ती में ÷सॉफ्टवेयर-फर्स्ट÷ की नीति अपनाती रहेंगी, तब तक विश्वविद्यालयों में तैयार होने वाली हार्डवेयर प्रतिभा बेकार पड़ी रहेगी। माँग और आपूर्ति दोनों तरफ से एक साथ काम होना जरूरी है।

भारत के पास इस क्षेत्र में वक्त कम है। फैब बनाने में पैसा लग रहा है, योजनाएँ बन रही हैं लेकिन जो चिप उन फैब में बनेगी। उम्मीद की किरण दिख रही है लेकिन असली परीक्षा अभी शेष है। बातें बहुत हो चुकी हैं। अब निर्माण का वक्त है।

लेखक के बारे में

डॉ नवीन कुमार, लंगट सिंह कॉलेज में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में फैकल्टी मेंबर हैं तथा भारत के सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्र के प्रयासों और प्रगति पर बारीक नजर रखते हैं।

शिक्षा के मंदिर में 'अहंकार' का तांडव, क्या न्याय कर पायेगा ''कानूनी आतंकवाद'' ?

लेखक–श्याम सिंह पंवार
वरिष्ठ पत्रकार ,पूर्व सदस्य प्रेस काउंसिल आफ इंडिया

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से सामने आया यह मामला केवल एक 'कहासुनी' नहीं, बल्कि हमारे समाज और प्रशासनिक व्यवस्था के गिरते स्तर का एक जीवन्त प्रमाण है। एक स्कूल परिसर, जिसे 'विद्या का मंदिर' कहा जाता है, आज निजी अहंकार और तुच्छ विवादों का अखाड़ा बन चुका है। अनेक सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल वीडियो में एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा एक छात्र की माँ से बेहद अभद्र भाषा में बात करती नजर आईं, जहाँ वह बार-बार 'यू शटअप' और 'गेट लॉस' जैसे कटु शब्दों का इस्तेमाल करती दिखीं। इतना ही नहीं, उन्होंने अभिभावक को बच्चे का नाम स्कूल रजिस्टर से काटने की धमकी भी दी, जिससे मामला और गम्भीर हो गया। बताया जा रहा है कि स्कूली फीस और बाहर से कॉपी-किताब खरीदने को लेकर विवाद शुरू हुआ था।

हालांकि, प्रिंसिपल ने सार्वजनिक रूप से माफी माँग ली है, लेकिन जाँच पूरी होने तक उनके स्कूल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अनेक खबरों की मानें तो, शिक्षा विभाग ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक, स्कूल को वर्ष 2009 में मान्यता दी गई थी और 2014 में कक्षा 6 से 8 तक की स्वीकृति भी दी गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जाँच में शिक्षा का अधिकार अधिनियम या अन्य नियमों का उल्लंघन पाया गया तो स्कूल की मान्यता पर भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल, 3 सदस्यीय जांच टीम को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करें।अब सवाल यह उठता है कि 2014 से अब तक यह क्यों नहीं पता किया गया कि स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम सहित अन्य नियमों का पालन किया जा रहा था या नहीं ? एक विवाद आने के बाद ही इसका खुलासा हुआ क्यों ?

शिक्षा के मंदिर में 'अहंकार' का तांडव

जब एक प्रिंसिपल और अभिभावक के बीच की बातचीत संवाद के बजाय विवाद का रूप ले ले, तो समझ लेना चाहिए कि नैतिकता की नींव हिल चुकी है। वीडियो में जो कुछ भी दिखा, वह केवल आवेश नहीं था, बल्कि वह अनुशासनहीनता थी जो आज के 'शिक्षित' और 'बुद्धजीवी' समाज की कड़वी सच्चाई है। एक शिक्षक का अपने पद की गरिमा गिराना किसी 'सामाजिक द्रोह' से कम नहीं है। एक प्रिंसिपल / एक शिक्षक, जिसका काम बच्चों को सभ्य, शिक्षित व संस्कारी बनाना है, यदि स्वयं सड़क छाप विवादों का हिस्सा बने, तो वह आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ गद्दारी कर रहा है। लेकिन, अगर एक सामान्य कहासुनी को संगीन आपराधिक धाराओं में बदला जा रहा है, तो यह उस तंत्र की विफलता है जो तथ्यों से ज्यादा शोर पर भरोसा करता है। न्याय का अस्त्र या प्रतिशोध का हथियार है एससी/एसटी एक्ट ? इस मामले में सबसे विवादास्पद पहलू एफ. आई. आर. में एससी/एसटी एक्ट का जोड़ा जाना है। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर यह सवाल उठना लाजमी है कि –क्या हर विवाद अब जाति के चश्मे से ही देखा जाएगा ?क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने केवल वीडियो देखकर या दबाव में आकर ये धाराएं लगाई हैं?क्या 'सामान्य जाति' का होना ही ममता मिश्रा के लिये एक 'अभिशाप' बन गया है ?''कानूनी आतंकवाद'' का सहारा कब तक ?– जब एक आपसी सामान्य विवाद को 'जातीय प्रताड़ना' का रंग दे दिया जाता है, तो असली पीड़ितों के साथ न्याय भले ही हो रहा है लेकिन दूसरे पक्ष के साथ अन्याय हो जाता है, क्योंकि उसे उस कृत्य की सजा दी जाती है जिसे उसने कारित ही किया नही अर्थात कानून का उपयोग जब निजी कुंठा निकालने के लिए होने लगे, तो वह न्याय नहीं, बल्कि जातीय चश्मे से देखा जाने लगे तो ऐसा कानून ''कानूनी आतंकवाद'' की श्रेणी में ही आने लगता है।

यदि कानून केवल एक पक्ष की जाति देखकर धाराओं की 'सजावट' करेगा और दूसरा पक्ष अपनी मर्यादा भूलकर विवाद को हवा देगा, तो न्याय, न्याय न होकर केवल एक कागजी कार्यवाही बनकर रह जाएगा।

खोखली होती जा रही मर्यादायें

उप्र के हरदोई का वायरल वीडियो चीख–चीख कर कह रहा है कि शिक्षा के व्यापारिक युग में अब न गुरु में वह 'धैर्य' बचा है और न समाज में गुरू के प्रति 'सम्मान' ।प्रिंसिपल महोदया हो या अभिभावक, दोष जिसका भी हो, सजा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए न कि 'जाति' के आधार पर। वहीं अगर एक शिक्षक ही समाज में विद्वेष फैलाए, तो वह राष्ट्र के नैतिक पतन की शुरुआत है। इसे नकारा नहीं जा सकता !

बिल्हौर में प्रगणकों की 'क्लास' तीन दिन में तैयार होगी पूरी टीम

जनगणना-2027 को सटीक व त्रुटिरहित बनाने पर जोर, 30 अप्रैल तक चलेगा तीन दिवसीय प्रशिक्षण

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। जनगणना-2027 को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार से डीपीएस स्कूल बिल्हौर में प्रगणक और सुपरवाइजरों का तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया। पहले दिन ही बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लेकर जनगणना की बारीकियों को समझा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए डीपीएस स्कूल के आठ कमरों में अलग-अलग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। यहां प्रगणकों और सुपरवाइजरों को घर-घर जाकर जानकारी जुटाने, डिजिटल माध्यम से डेटा फीडिंग और फार्म भरने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

तहसीलदार अनुभव चंद्रा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सिर्फ सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं बल्कि व्यवहारिक अभ्यास भी कराया जा रहा है। उन्हें संभावित समस्याओं और उनके समाधान के बारे में भी बताया जा रहा है, ताकि वास्तविक सर्वे के दौरान किसी तरह की दिक्कत न आए। यह प्रशिक्षण 28 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। तीन दिन में सभी प्रगणकों और सुपरवाइजरों को पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे जनगणना का काम तय समय पर और बिना त्रुटि के पूरा किया जा सके। पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम की मॉनीटरिंग उप जिलाधिकारी बिल्हौर मनीष कुमार , तहसीलदार अनुभव चंद्रा , नायब तहसीलदार चंद्र प्रकाश राजपूत,और खंड शिक्षा अधिकारी बिल्हौर रवि कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

प्रशिक्षण कक्षा का निरीक्षण करते अधिकारी

प्रशिक्षण में मौजूद प्रगणक व सुपरवाइजर

- प्रशिक्षण के पहले दिन 41 प्रगणक गायब, डीपीएस स्कूल के आठ कमरों में बनाए गए अलग-अलग सत्र

जनगणना को लेकर प्रशासन गंभीर

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनगणना-2027 एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है, जिसे पूरी सटीकता और पारदर्शिता के साथ पूरा करना प्राथमिकता है। इसके लिए जमीनी स्तर पर कर्मचारियों को दक्ष बनाना सबसे जरूरी है, और यही उद्देश्य इस प्रशिक्षण के जरिए पूरा किया जा रहा है।

पहले ही दिन 41 प्रगणक अनुपस्थित, प्रशासन सख्त: जनगणना-2027 के तहत डीपीएस स्कूल में चल रहे प्रशिक्षण के पहले ही दिन लापरवाही सामने आई। करीब 380 प्रगणकों में से 339 प्रशिक्षण में उपस्थित रहे, जबकि 41 प्रगणक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए। इस पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए नाराजगी जताई है। अधिकारियों का कहना है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुपस्थित प्रगणकों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तहसीलदार संग सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाते बीईओ व डीपीएस प्रधानाचार्य

प्रगणक-सुपरवाइजर के लिए बने भोजन को एसडीएम ने चखा

डीपीएस स्कूल में चल रहे जनगणना-2027 प्रशिक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। प्रशिक्षण में शामिल प्रगणक और सुपरवाइजर के लिए बनाए गए भोजन की गुणवत्ता जांचने खुद एसडीएम मौके पर पहुंचे और भोजन चखकर उसकी शुद्धता परखी।निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टेबल-कुर्सियों की समुचित व्यवस्था कराई गई, ताकि प्रशिक्षण सुचारू रूप से संचालित हो सके। एसडीएम ने साफ-सफाई, खानपान और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में शामिल सभी कर्मियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त रहनी चाहिए।

एसडीएम के आदेशों को टोल पर ठेंगा, प्रशिक्षण कर्मियों से वसूला गया शुल्क

जनगणना-2027 प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण कर्मियों से टोल न वसूले जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन मंगलवार को टोल प्लाजा पर उनसे शुल्क वसूला गया। इस पर प्रशिक्षण कर्मियों ने तहसील प्रशासन को अवगत कराया। शिकायत है कि तहसील अधिकारियों की बात भी टोल कर्मियों ने नहीं मानी। मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।

एसडीएम की डिजिटल सखी से तहसील में हड़कंप, लापरवाहों की बढ़ी टेंशन

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। तहसील बिल्हौर में नवागत उपजिलाधिकारी मनीष कुमार ने कार्यभार संभालते ही प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लानी शुरू कर दी है। उनकी डिजिटल सख्ती और सक्रिय कार्यशैली से राजस्व विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है। लंबे समय से चली आ रही लापरवाही और देरी पर अब अंकुश लगता नजर आ रहा है।

एसडीएम मनीष कुमार प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल माध्यम का सहारा ले रहे हैं। वे प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर आदेश देने के बाद उसकी कॉपी तत्काल अपने मोबाइल में स्कैन कर सुरक्षित कर लेते हैं। इससे अब फाइल गुम होने या आदेश प्राप्त न होने जैसे बहाने खत्म हो गए हैं। कार्यालय से फाइल आगे बढ़ते ही संबंधित लेखपाल और राजस्व निरीक्षक से सीधे फोन पर संपर्क कर प्रगति की जानकारी ली जा रही है। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस 'रियल टाइम' मॉनिटरिंग से कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो रही है और कार्य में तेजी आई है।

- हर फाइल की मोबाइल में रिकॉर्डिंग, 'गुम' होने का बहाना खत्म
- फोन पर सीधे निर्देश, रियल टाइम मॉनिटरिंग से तेज हुआ निस्तारण

फरियादियों में बढ़ा भरोसा

तहसील परिसर पहुंचे फरियादियों का कहना है कि एसडीएम स्वयं प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर रहे हैं और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और लोगों की सीधे सुनवाई होने लगी है, जिससे न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है।

एक ही चिता पर पिता-पुत्र का अंतिम संस्कार, पूरा गांव शोक में डूबा

स्वराज इंडिया फालोअप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। सरैया के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद फत्तेपुर गांव में पसरा मातम थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को पिता-पुत्र का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किए जाने के बाद भी गांव का माहौल गमगीन बना हुआ है। बुधवार को भी पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहा और शोक संतप्त परिवार के घर लोगों का तांता लगा रहा।

बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल को ककवन क्षेत्र के फत्तेपुर निवासी कमलेश (54) और उनके पुत्र अंकुर (19) की बाइक दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी। दोनों कन्नौज से घर लौट रहे थे, तभी

रास्ते में हादसा हो गया। जिस दिन यह हादसा हुआ, उसी दिन घर में तिलक समारोह की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन खुशी का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया।मंगलवार को जैसे ही दोनों के शव गांव पहुंचे, चीख-पुकार से माहौल दहल उठा। परिजन और महिलाएं गश खाकर गिर पड़ीं। देर शाम एक ही चिता पर पिता-पुत्र का अंतिम संस्कार किया गया, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं।

बुधवार को भी परिवार का कोई सदस्य इस सदमे से उबर नहीं सका। परिजन बार-बार हादसे को याद कर बिलख उठते हैं, वहीं गांव की महिलाएं अब भी गम में डूबी हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना ने पूरे गांव को अंदर तक झकझोर दिया है। हर कोई पीड़ित परिवार के साथ खड़ा नजर आ रहा है।

बसपा नेताओं ने जताई संवेदना

बहुजन समाज पार्टी के विनय गौतम, जीवनलाल, प्रेमचंद्र और ओमप्रकाश समेत अन्य पदाधिकारी फत्तेपुर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। इस दौरान बसपा के प्रभारी विनय गौतम भी भावुक हो उठे। नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग भी की।

पश्चिमी विक्षोभ का असर: यूपी में 4 मई तक बारिश-आंधी का अलर्ट, 58 जिलों में चेतावनी

तेज हवाओं संग गरज-चमक, तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस गिरावट, गर्मी से राहत लेकिन उमस बढ़ने के आसार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और आंधी का दौर शुरू हो गया है। बुधवार सुबह नोएडा, मथुरा, बरेली, संभल समेत आधा दर्जन जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी यूपी के अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहे। नोएडा में तड़के तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, वहीं मथुरा में अचानक बारिश से बचने के लिए लोग ट्रॉलियों के नीचे शरण लेते नजर आए। सहारनपुर और मेरठ में भी रुक-रुक कर बूंदाबांदी होती रही।

लखनऊ स्थित मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह के अनुसार प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले पांच दिन यानी 4 मई तक मौसम अस्थिर रहेगा। इस दौरान तेज हवाओं के साथ गरज-चमक वाली बारिश होती रहेगी। इससे भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी तथा तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आएगी। हालांकि दिन में धूप निकलने पर उमस जैसी स्थिति भी बन सकती है।

अमरोहा में आधी रात को मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।

हालांकि कई जगह पेड़ों की टहनियां टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरें भी सामने आई हैं। दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल तेज धूप बनी हुई है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण लोगों को कुछ राहत महसूस हो रही है।

मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं भी मौसम परिवर्तन की बड़ी वजह हैं। विभाग ने पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के 58 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है, जिससे सतर्क रहने की अपील की गई है। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश के 15 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया था। बांदा 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा, हालांकि यहां तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई।

गाजियाबाद में 15 मंजिला इमारत में भीषण आग, चार मंजिलें चपेट में

इंदिरापुरम की सोसायटी में मचा हड़कंप, दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

गाजियाबाद। इंदिरापुरम इलाके में बुधवार सुबह एक 15 मंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना अभय खंड स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसायटी की है, जहां सुबह करीब 8:30 बजे बिल्डिंग के 9वें फ्लोर पर अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ऊपर की तीन अन्य मंजिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया।आग लगते ही बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। धुएं का घना गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धुआं करीब 2 किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। फ्लैट में रह रहे लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरकर बाहर निकल आए। इस दौरान सोसायटी परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि, बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में आग लगने के कारण दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऊंचाई अधिक होने से आग तक पहुंचने और उसे नियंत्रित करने में समय लग रहा है।पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है।

एहतियात के तौर पर पूरी बिल्डिंग और आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया है। निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है और हालात पर नजर बनाए हुए है।

11 नए एक्सप्रेस-वे की तैयारी यूपी में भूमि अधिग्रहण शुरू

गंगा एक्सप्रेस-वे के बाद सरकार का बड़ा कदम, औद्योगिक कनेक्टिविटी और निवेश बढ़ाने पर फोकस

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में 11 नए एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाल ही में गंगा एक्सप्रेस-वे के पूरा होने के बाद सरकार अब सड़क नेटवर्क के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है। इसके तहत संबंधित विभागों को भूमि की पहचान, सर्वेक्षण और अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।सरकार का मानना है कि ये नए एक्सप्रेसवे प्रदेश के औद्योगिक, व्यापारिक और कृषि क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ेंगे। इससे यात्रा समय में कमी आएगी और माल परिवहन अधिक तेज व सस्ता होगा। खासतौर पर लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इससे बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उद्योगों की लागत घटेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की भी योजना है। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर, वेयरहाउसिंग और नए व्यापारिक केंद्र विकसित किए जाएंगे। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में शामिल हो सकेगा।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह पारदर्शी और कानूनसम्मत होगी। 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम के तहत किसानों और भूमि मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए विशेष पैकेज भी तैयार किए जा रहे हैं।

सर्वेक्षण टीमें गांव-गांव जाकर जमीन का आकलन कर रही हैं और प्रभावित लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक्सप्रेसवे परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की रीढ़ साबित होंगी। बेहतर कनेक्टिविटी से प्रदेश का औद्योगिक ढांचा मजबूत होगा और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए नए अवसर खुलेंगे।

कहां-कहां बनेंगे नए एक्सप्रेस-वे

- पूर्वांचल और बुंदेलखंड को जोड़ने वाला नया कॉरिडोर
- पश्चिमी यूपी से मध्य यूपी तक तेज कनेक्टिविटी मार्ग
- औद्योगिक क्लस्टरों को जोड़ने वाले रिंग एक्सप्रेसवे
- प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे
- पूर्वी यूपी से बिहार सीमा तक विस्तारित मार्ग
- बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदरूनी जिलों को जोड़ने वाले मार्ग
- दिल्ली-एनसीआर से सटे क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे
- गंगा किनारे के जिलों को जोड़ने वाला समानांतर मार्ग
- कृषि उत्पाद परिवहन के लिए विशेष लॉजिस्टिक एक्सप्रेसवे
- पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे नेटवर्क
- औद्योगिक गलियारों के साथ विकसित होने वाले नए हाई-स्पीड मार्ग

सर्राफा व्यापारी से लूट का खुलासा, पुलिस ने 3 बदमाश दबोचे

» सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन से खुला राज

» तमंचा, नकदी व बुलेट बरामद, एक आरोपी फरार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े सर्राफा व्यापारी से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए पर्दाफाश कर दिया। गजनेर थाना और एसओजी टीम की संयुक्त मुहिम में तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूट की नकदी, मोबाइल फोन, अवैध असलहा और

घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

बताया गया कि 26 अप्रैल को शाहजहांपुर निवासी सर्राफा व्यापारी जलालुद्दीन दुकान बंद कर दोपहर करीब एक बजे घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे तीन बदमाशों ने काले रंग की बुलेट से उनका रास्ता रोक लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और करीब 20 हजार रुपए, मोबाइल फोन, कार्ड होल्डर समेत अन्य सामान लूटकर फरार हो गए।

घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्ध मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस की। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर सरवनखेड़ा-गंगरैली मार्ग पर चेकिंग के दौरान तीन बदमाशों को धर दबोचा गया। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11,400 रुपए नकद, दो देसी तमंचे (315 बोर), चार जिंदा कारतूस, लूट के मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजरोशन, आकाश कोरी और कुलदीप कोरी के रूप में हुई है, जबकि श्याम कोरी नाम का आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधीक्षक ने इस सफल कार्रवाई पर टीम को 10 हजार रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहीं फरार आरोपी की तलाश जारी है।

तमंचा लेकर जा रहा युवक गिरफ्तार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। थाना रनियां पुलिस ने एक युवक को अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 28 अप्रैल 2026 को संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कटका रोड स्थित शिवा होटल एंड रेस्टोरेंट के पास एक युवक को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से .315 बोर का अवैध तमंचा बरामद हुआ।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपू सिंह निवासी किसरवल रोड रनियां बताया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

टप्पेबाजों ने पेट्रोल पम्प कर्मचारी से 1500 रुपये ठगे

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मूसानगर थाना क्षेत्र में टप्पेबाजों की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है। पुलन्दर मोड़ के पास स्थित धर्मवीर राजावत पेट्रोल पम्प पर मंगलवार शाम दो शातिर युवकों ने बड़ी ही चालाकी से पम्प कर्मचारी को अपने झांसे में लेकर 1500 रुपये ठग लिए और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि पूरी वारदात पम्प पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पम्प मालिक धर्मवीर रजावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार शाम करीब 6-30 बजे एक काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक पम्प पर पहुंचे। खुद को जानकार बताते हुए ऑयल, डीजल और पेट्रोल की गुणवत्ता व क्षमता की जांच करने की बात करने लगे। टप्पेबाजों ने इस दौरान कर्मचारी से 1500 रुपये ले लिए और भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान कर रही है। थाना प्रभारी रीना गौतम ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।

25 साल पुरानी मोटर ने तोड़ा दम, तीन महीने से ठप ट्यूबवेल, सिंचाई संकट में घिरे किसान

100 बीघा खेती प्रभावित, मूंग-चरी सूखने की कगार पर, शिकायतों के बावजूद विभाग बेपरवाह

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। ब्लॉक सरवनखेडा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिल्टी में स्थित 93 एजी बोर का सरकारी ट्यूबवेल पिछले तीन महीनों से बंद पड़ा है, जिससे किसानों के सामने गंभीर सिंचाई संकट खड़ा हो गया है। इस ट्यूबवेल पर लगभग 100 बीघा कृषि भूमि निर्भर है, जिसमें 30 बीघा में बोई गई मूंग और 20 बीघा में खड़ी चरी की फसल पानी के अभाव में सूखने की कगार पर पहुंच गई है। शेष भूमि भी सिंचाई न होने के कारण बंजर जैसी स्थिति में बदलती जा रही है।

ग्रामीणों के अनुसार, बीते करीब 25 वर्षों से इसी ट्यूबवेल की जर्जर मोटर को मरम्मत के सहारे चलाया जाता रहा, लेकिन इस बार मोटर पूरी तरह जवाब दे चुकी है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारियों जेई, एई और एक्सईएन को समस्या से अवगत कराया, बावजूद इसके अब तक नई मोटर की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।

स्थिति को और गंभीर बनाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि विभाग न तो मोटर निकालने के लिए श्रमिक उपलब्ध कराता है और न ही मजदूरी का भुगतान करता है। ऐसे में ट्यूबवेल की मरम्मत कराना किसानों के लिए लगभग असंभव हो गया है। जब संबंधित जेई सुजीत कुशवाहा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। कई बार कॉल करने के बावजूद उनका पक्ष सामने नहीं आ सका।सिंचाई संकट के कारण किसानों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि यदि जल्द ही नई मोटर लगाकर ट्यूबवेल चालू नहीं किया गया, तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। एक ओर किसान अपनी आजीविका बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

चुनाव की तैयारी तेज, कमलेश दिवाकर की सक्रियता चर्चा में

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व विधायक कमलेश चंद्र दिवाकर इन दिनों रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क और भ्रमण कर रहे हैं।

उनके सक्रिय दौरे और लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रहे है।बीते दिनों कमलेश दिवाकर ने क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर नई मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। साथ ही उन्होंने समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिया।

जनसंपर्क अभियान के तहत उन्होंने आधा दर्जन से अधिक गांवों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद स्थापित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने भी उनकी बातों को गंभीरता से सुना और समर्थन जताया। जनता से मिल रहे समर्थन पर कमलेश चंद्र दिवाकर ने आभार जताते हुए कहा कि रसूलाबाद क्षेत्र की जनता से उन्हें हमेशा स्नेह और सहयोग मिला है। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और सरकारी योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंच रही हैं। लगातार बढ़ती सक्रियता के चलते क्षेत्र में उनकी राजनीतिक गतिविधियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

इसी जगह पर बनेगा पुल

प्रधान की मांग पर बनेगा सेंगर नदी पर पुल !

जगदीश निषाद ग्राम प्रधान-भरतौली

शंकर सिंह स्वराज इंडिया ब्यूरो

मलासा अंतर्गत ग्राम भरतौली और चतुरीपुरवा पड़ांव के बीच बनेगा पुल, 20.89 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा

कानपुर देहात। भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड मलासा अंतर्गत ग्राम भरतौली और चतुरीपुरवा पड़ांव के बीच बहने वाली सेंगर नदी पर पुल निर्माण की मांग ने रफ्तार पकड़ ली है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, सेतु निर्माण इकाई कानपुर ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है।उप परियोजना प्रबंधक द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्र के अनुसार, ग्राम भरतौली केवटान से सिहारी गौशाला के मध्य सेंगर नदी पर पुल निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

इसे वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना में शामिल करते हुए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गईं।जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा 9 मई 2025 को प्रस्ताव को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को अनुमोदन के लिए अग्रसारित किया गया। इसके बाद लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के मुख्य अभियंता (सेतु) द्वारा तकनीकी आकलन करते हुए करीब 2089.19 लाख रुपये (लगभग 20.89 करोड़ रुपये) की लागत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

फिलहाल प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक में इस पर मुहर लग सकती है।ग्राम प्रधान भरतौली, जगदीश निषाद ने बताया कि पुल के अभाव में क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को हर रोज जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है।

बरसात के मौसम में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। पुल बनने से आवागमन सुगम होगा

और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।स्थानीय लोगों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए।

बाइक फिसलने से महिला की मौत, परिवार में मचा कोहराम

» परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए महिला का अंतिम संस्कार किया

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। जनपद के राजपुर क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई। जल्लापुर गांव के सामने मुगल रोड पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, सटटी थाना क्षेत्र के ततारपुर डेरा गांव निवासी चिंटू सिंह अपनी पत्नी अंगूरी देवी के साथ राजपुर कस्बा बाजार से घर लौट रहे थे। तभी जल्लापुर गांव के पास अचानक बाइक फिसल गई और दोनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे में अंगूरी देवी को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद राहगीरों की मदद से दोनों को तत्काल राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने अंगूरी देवी को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए ही महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं, राजपुर थानाध्यक्ष सनत कुमार ने बताया कि घटना की कोई आधिकारिक सूचना पुलिस को नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

महिला चौपाल: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का दिया संदेश

» अंडवा गांव में एक उम्मीद जनकल्याण सेवा समिति ने किया आयोजन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

कानपुर देहात। मलासा विकास खंड के अंडवा गांव में समाजसेविका मां पीतांबरा हॉस्पिटल की संचालिका, साथ ही एक उम्मीद जनकल्याण सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सीता यादव के नेतृत्व में महिला चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चं ने भाग लिया।चौपाल में पहुंचने पर महिलाओं ने डॉ. सीता यादव का माल्यार्पण कर एवं अंगवस्त्र पहनाकर जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि सशक्त बनने के लिए आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। उन्होंने महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए और अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि वे भविष्य में आगे बढ़ सकें। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि ÷शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो÷ के मार्ग पर चलकर ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है।डॉ. सीता यादव ने एक उम्मीद जनकल्याण सेवा समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है, साथ ही क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयासरत है। कार्यक्रम के अंत में संस्था की ओर से महिलाओं को कैलेंडर वितरित किए गए तथा बच्चों को शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। स्टेशनरी पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर संस्था के जिला उपाध्यक्ष महेन्द्र पाल, ऋषभ यादव, नमन, आयुष, रेखा देवी, सुमन पाल, सुषमा देवी, रंजू पाल, सरिता, लक्ष्मी देवी, सोनी, शारदा, उर्मिला, दीपिका, केशकुमारी, पुष्पा देवी, आकांक्षा, कंचन, रेनू, रिचा, शांति, राधा, सुमन सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे मौजूद रहे।

महोबा: पद के बदले बिस्तर वाले विवाद में समझौता

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

महोबा।महोबा जनपद में पिछले दो दिनों से सुर्खियों में बना भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विवाद फिलहाल थमता नजर आ रहा है। जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा और पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी के बीच चले तीखे आरोप-प्रत्यारोप के बाद प्रदेश नेतृत्व की सक्रियता से दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई अहम सवाल अब भी चर्चा में हैं।

» भाजपा जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर लगे थे गंभीर आरोप

» 48 घंटे में बदला घटनाक्रम, प्रदेश नेतृत्व की मध्यस्थता से दोनों पक्ष आमने-सामने आए

दरअसल, 26 अप्रैल को दीपाली तिवारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी में हलचल मचा दी थी। उन्होंने जिलाध्यक्ष पर पद के बदले आपत्तिजनक प्रस्ताव देने और मना करने पर धमकी देने का आरोप लगाया था। यह मामला तेजी से पूरे बुंदेलखंड में चर्चा का विषय बन गया।

इसके अगले ही दिन 27 अप्रैल को दीपाली तिवारी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचीं, जिसके बाद मामला और तूल पकड़ गया। पार्टी की छवि पर पड़ रहे असर को देखते हुए भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने तत्काल संज्ञान लिया और जांच व सुलह के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों को महोबा भेजा।

प्रदेश उपाध्यक्ष कमलवती सिंह और क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे ने महोबा पहुंचकर दोनों पक्षों से अलग-अलग और संयुक्त वार्ता की।

लंबी बातचीत और मध्यस्थता के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इसके बाद एक साथ मंच पर आए नेताओं की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई।

सवाल अब भी बरकरार

हालांकि समझौते के साथ विवाद पर तत्काल विराम जरूर लग गया है, लेकिन कई सवाल अब भी उठ रहे हैं। क्या यह समझौता स्वेच्छा से हुआ या किसी दबाव में? महिला सम्मान और सुरक्षा से जुड़े आरोपों पर क्या निष्पक्ष जांच होगी? और भविष्य में इस तरह के मामलों में पार्टी का रुख कितना सख्त रहेगा?राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला केवल संगठनात्मक विवाद नहीं, बल्कि पार्टी की आंतरिक कार्यप्रणाली और महिला कार्यकर्ताओं की सुरक्षा से भी जुड़ा है। ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व की कार्रवाई और रुख पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।

मंत्री अजीत पाल की महोबा विवाद पर चुप्पी, 'मुझे कुछ पता नहीं'

फतेहपुर में महिला आरक्षण पर प्रेस वार्ता, लेकिन महोबा प्रकरण पर जवाब से बचते दिखे मंत्री

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फतेहपुर।भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिला आरक्षण को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता उस समय सियासी मोड़ ले गई, जब पत्रकारों ने महोबा में भाजपा महिला पदाधिकारी द्वारा जिलाध्यक्ष पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर सवाल दाग दिए।

प्रेस वार्ता में मौजूद अजीत सिंह पाल इन सवालों पर असहज नजर आए और सीधे जवाब देने के बजाय सिर्फ इतना कहकर बात टाल दी कि 'मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है।

'पत्रकार परमानंद ने जब लगातार इस मुद्दे पर जवाब मांगा तो मंत्री की खामोशी और भी गहरी हो गई। मंच पर मौजूद अन्य नेताओं ने भी इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी।

गौरतलब है कि महोबा में भाजपा की एक महिला पदाधिकारी ने जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से पार्टी के भीतर हलचल तेज है। ऐसे में प्रदेश के प्रभारी मंत्री का इस पूरे प्रकरण से अनभिज्ञ होना कई सवाल खड़े कर रहा है।राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा इस बात की है कि क्या वाकई मंत्री को पूरे मामले की जानकारी नहीं थी, या फिर विवाद से बचने के लिए उन्होंने अनजान बनने का रास्ता चुना।

राज्य मंत्री का तरह के गंभीर आरोपों पर स्पष्ट रुख न लेना पार्टी की छवि पर असर डाल सकता है।

जनगणना 2027: गणनाकर्मी का न करें इंतजार, खुद करें स्वगणना

लंबी पूछताछ से मिलेगी मुक्ति

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। भारत में अगली जनगणना साल 2027 में होने जा रही है जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और पहली बार 16 भाषाओं में सेल्फ एन्यूमेरेशन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकते हैं। 2026ङ्क27 की जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इस बार कई बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। साल 2027 में पूरी होने वाली जनगणना की प्रक्रिया तेजी से गतिमान है। इस बार जनगणना कई मायनों में खास होगी क्योंकि इसे डिजिटल तरीके से कराने की योजना है हालांकि इसकी प्रक्रिया 2026 से ही शुरू हो चुकी है और इसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें पहले घरों का सर्वे और फिर जनसंख्या की गिनती की जाएगी। इस कर को करने वालों को 25000 रुपए प्रदान किए जाएंगे।

बता दें कि भारत में जनगणना का काम केंद्र सरकार के अधीन होता है। इसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। जनगणना के लिए अलग से बड़ी संख्या में नए कर्मचारियों की हायरिंग नहीं होती है बल्कि आमतौर पर सरकारी स्कूलों के शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षामित्र, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, क्लर्क और अन्य सरकारी कर्मचारी इस काम में लगाए गए हैं। वहीं अगर सैलरी की बात करें तो जनगणना करने वालों को अलग से स्थायी सैलरी नहीं मिलती क्योंकि वे पहले से सरकारी कर्मचारी होते हैं। उन्हें काम के बदले मानदेय दिया जाता है। एन्यूमरेटर को करीब 25000 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। लोग खुद भी ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे। इस प्रक्रिया में हर परिवार को एक विशिष्ट 11 अंकों की स्श्व ढ्ढष्ठ मिलेगी जो न सिर्फ आपकी पहचान को सुरक्षित रखेगी बल्कि जनगणना की पूरी प्रक्रिया को बेहद सटीक और पारदर्शी बना देगी। यह सिर्फ लोगों की गिनती नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया के सफर में एक मील का पत्थर है जो भविष्य की सरकारी नीतियों और रिसर्च के लिए एक पुख्ता आधार तैयार करेगा।

होम्योपैथिक अस्पताल का अभाव, मरीज बेहाल

इलाज के लिए दूर-दराज भटकने को मजबूर लोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाई मांग

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर नगर, जो प्रयागराज, जौनपुर और प्रतापगढ़ जैसे तीन महत्वपूर्ण जनपदों के बीच स्थित है, आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है।

लाखों की आबादी वाले इस नगर में होम्योपैथिक अस्पताल न होने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका क्षेत्र होने और निकट स्थित औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया के कारण इस कस्बे का महत्व और बढ़ जाता है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि होम्योपैथिक चिकित्सा सस्ती, सुरक्षित और बिना साइड इफेक्ट के होती है।

सर्दी-जुकाम, त्वचा रोग, पुराना दर्द और ऊर्जा से जुड़ी समस्याओं में लोग इस पद्धति पर खासा भरोसा करते हैं। बावजूद इसके, अस्पताल के अभाव में मरीजों को जौनपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि वे दूर जाकर इलाज कराने में असमर्थ रहते हैं। लोगों का कहना है कि मुंगराबादशाहपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएससी) में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, जहां आसानी से होम्योपैथिक अस्पताल खोला जा सकता है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं इंजीनियर व सभासद उमाशंकर गुप्ता, अनिल विश्वकर्मा, योगेश कुमार गुप्त और नवल किशोर गुप्त सहित अन्य लोगों ने जिला प्रशासन से शीघ्र अस्पताल स्थापित कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आम जनता की परेशानियां और बढ़ेंगी।

सरकारी पर्चे पर 'कमीशन का खेल'! अयोध्या जिला अस्पताल में डॉक्टर की नई टेक्निक

» बाहर की दवा लिखो फिर पेन से काट दो! मरीज बोले, 'काटा नाम, लेकिन दवा वही खरीदनी पड़ी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य विभाग चाहे जितने सख्त आदेश जारी कर लें कि सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवा लिखना पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन अयोध्या जिला अस्पताल में कुछ डॉक्टरों ने सिस्टम को ही 'चकमा' देने की नई तकनीक खोज निकाली है।जिला अस्पताल के आर्थो विभाग में हाल ही में तैनात एक डॉक्टर पर आरोप है कि वे मरीजों को बाहर की दवाएं लिख रहे हैं, लेकिन सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए बाद में उसी दवा के नाम पर पेन चला देते हैं। यानी रिकॉर्ड में ऐसा दिखेगा कि डॉक्टर ने दवा काट दी, लेकिन मरीज को इशारा साफ रहता है—दवा बाहर से ही खरीदनी है।मरीजों का आरोप है कि जिन दवाओं के नाम काटे जाते हैं, वही दवाएं मेडिकल स्टोर से खरीदने का दबाव बनाया जाता है। चर्चा यह भी है कि इन दवाओं पर मोटे कमीशन का खेल चलता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा उपलब्ध कराने और बाहर की दवा पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, तब आखिर ऐसे खेल कैसे चल रहे हैं? यह मामला सिर्फ एक डॉक्टर पर आरोप भर नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जहां आदेश फाइलों में सख्त दिखते हैं और जमीन पर मरीजों की जेब कटती रहती है। अगर आरोप सही हैं, तो क्या स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा या फिर मरीज यूं ही 'काटे हुए पर्चों' के सहारे लुटते रहेंगे?

अयोध्या से मुंबई के लिए अमृत भारत ट्रेन शुरू, सफर होगा सस्ता और आसान

पीएम मोदी ने काशी से दिखाई हरी झंडी, अयोध्या धाम स्टेशन से विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किया रवाना

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या से मुंबई टर्मिनल के लिए नई अमृत भारत ट्रेन का संचालन मंगलवार से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जबकि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने ट्रेन को रवाना किया।

विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने इसे क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि यह ट्रेन खासतौर पर मध्यम और निम्न वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इससे कम खर्च में लंबी दूरी की यात्रा आसान होगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या से मुंबई की सीधी कनेक्टिविटी मिलने से श्रद्धालुओं, व्यापारियों और आम यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। ट्रेन में जनरल और स्लीपर कोच लगाए गए हैं। लगभग 1500 किलोमीटर का सफर करीब 26 घंटे 20 मिनट में पूरा होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए एलईडी लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरे, बेहतर सीटिंग व्यवस्था और स्वच्छ शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

लक्ष्मण पथ के साये में उजड़ते घर! 250 निषाद परिवारों पर विस्थापन का संकट

» 60 साल से बसे आशियाने खतरे में, न जमीन, न मकान; पहले पुनर्वास की उठी मांग

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी में विकास की रफ्तार के बीच अब इंसानी दर्द भी सामने आने लगा है। गुप्तारघाट से राजघाट तक बन रहे करीब 9 किलोमीटर लंबे लक्ष्मण पथ के निर्माण ने 250 निषाद परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है।

सरयू किनारे जमथरा माझा में पिछले 60-70 वर्षों से रह रहे ये परिवार अब उजड़ने की कगार पर हैं। निर्माण कार्य तेज होते ही इन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि न तो उन्हें जमीन दी गई और न ही रहने के लिए मकान की कोई व्यवस्था की गई। निषाद समाज के लोगों का साफ कहना है ÷पहले पुनर्वास, फिर विस्थापन।÷ कई बार जिला प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है।वहीं विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भरोसा दिलाया है कि सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है क्या अयोध्या का विकास इन परिवारों के आंसुओं की कीमत पर होगा, या फिर इन्हें भी न्याय मिलेगा?

पेट्रोल-डीजल भरपूर, गैस में 7 दिन से ज्यादा देरी नहीं

समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए तेल कंपनियों को आपूर्ति निर्बाध रखने के निर्देश, घर-घर वितरण पर जोर

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) योगानंद पांडेय, जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश मिश्रा के साथ आईओसी,भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान कंपनियों ने बताया कि जनपद में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता संतोषजनक है और आपूर्ति लगातार जारी है। इस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। घरेलू रसोई गैस को लेकर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकतम 7 दिन का ही लंबित वितरण स्वीकार करते हुए गैस एजेंसियों को शत-प्रतिशत घर-घर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही गोदाम से सीधे उपभोक्ताओं को सिलेंडर देने पर रोक लगाने को कहा।जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की कि वे अपने घर पर ही वितरण के माध्यम से गैस प्राप्त करें, जिससे व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

मकबरा फ्लाईओवर पर 'वसूली राज'! ई-रिक्शा चालकों से टैक्स के नाम पर खेल

नगर निगम का दावा या फर्जी उगाही? 'नगर पालिका फैजाबाद' की पुरानी रसीदों ने खड़े किए सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी में अब ई-रिक्शा चालकों की जेब पर 'टैक्स' के नाम पर कैंची चलने लगी है। मामला मकबरा फ्लाईओवर के पास का है, जहां गुजरने वाले ई-रिक्शा चालकों से कथित तौर पर वसूली की जा रही है। वसूली करने वाले लोग इसे नगर निगम का टैक्स बता रहे हैं, लेकिन जो रसीद दी जा रही है, उसने पूरे खेल पर सवाल खड़े कर दिए हैं।सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रसीद पर

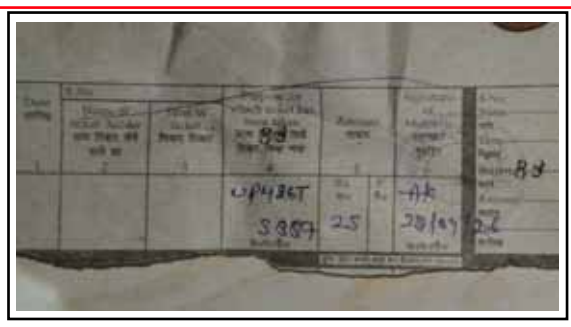

आज के नगर निगम अयोध्या का नहीं, बल्कि पुराने दौर के नगर पालिका फैजाबाद का नाम दर्ज है। ऐसे में चालक पूछ रहे हैं जब नगर पालिका का अस्तित्व ही खत्म हो चुका, तो फिर उसी नाम की रसीद आखिर कैसे काटी जा रही है? ई-रिक्शा चालकों का आरोप है कि उनसे रोजाना जबरन पैसा लिया जा रहा है। विरोध करने पर दबाव बनाया जाता है। कई चालक इसे खुलेआम अवैध उगाही बता रहे हैं।अब बड़ा सवाल नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। क्या यह अधिकृत वसूली है? अगर हां, तो पुरानी रसीदें क्यों? और अगर नहीं, तो आखिर किसके संरक्षण में यह खेल चल रहा है? सवाल है कि क्या रामनगरी में अब सड़क किनारे 'टैक्स सिंडिकेट' सक्रिय हो चुका है? और क्या जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले से अनजान हैं या फिर आंखें मूंदे बैठे हैं?

ऑस्ट्रेलिया का डिजिटल दिग्गजों पर शिकंजा खबरों के लिए 2.25% टैक्स का प्रस्ताव

सरकार का मकसदः मीडिया संस्थानों को आर्थिक मजबूती, कंपनियों का विरोध तेज

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मेटा, गूगल और टिकटॉक जैसी दिग्गज कंपनियों पर 2.25त्न टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य इन कंपनियों को समाचार संस्थानों और पत्रकारों को उचित भुगतान करने के लिए बाध्य करना है। सरकार का मानना है कि डिजिटल कंपनियां पत्रकारों की सामग्री का इस्तेमाल कर भारी मुनाफा कमाती हैं, लेकिन उसके बदले मीडिया संस्थानों को पर्याप्त आर्थिक सहयोग नहीं मिलता।

मंगलवार को जारी ड्राफ्ट कानून के अनुसार, यदि ये कंपनियां समाचार संगठनों के साथ व्यावसायिक समझौते नहीं करती हैं, तो उनकी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कुल आय पर 2.25% टैक्स लगाया जाएगा। सरकार इस विधेयक को 2 जुलाई तक संसद में पेश करने की तैयारी में है।

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने स्पष्ट कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र की नींव है और इसके लिए आर्थिक समर्थन जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां समाचार सामग्री से लाभ कमाएं और पत्रकारों को उसका उचित हिस्सा न मिले।

यह ऑस्ट्रेलिया का दूसरा बड़ा प्रयास है। इससे पहले 2021 में लागू न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड के तहत कंपनियों पर दबाव बनाया गया था। उस समय कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने समाचार संस्थानों के साथ समझौते किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इन समझौतों को आगे बढ़ाने से बचने के लिए प्लेटफॉर्म से समाचार सामग्री हटानी शुरू कर दी।

अब सरकार 'समाचार सौदेबाजी प्रोत्साहन' नामक नए प्रावधान के जरिए कंपनियों को फिर से बातचीत की मेज पर लाना चाहती है। यदि कंपनियां पत्रकारिता के लिए भुगतान करने पर सहमत होती हैं, तो उन्हें टैक्स में छूट भी दी जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से हर साल 200 से 250 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की राशि जुटाई जा सकती है, जिसे समाचार संस्थानों के बीच उनके पत्रकारों की संख्या के आधार पर बांटा जाएगा। हालांकि, इस प्रस्ताव का डिजिटल कंपनियों ने कड़ा विरोध किया है। मेटा ने इसे जबरन संपत्ति हस्तांतरण बताया है, जबकि गूगल ने कहा कि यह नीति बदलते डिजिटल विज्ञापन बाजार को समझने में विफल है। गूगल ने यह भी सवाल उठाया कि माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपचैट और ओपनएआई जैसे प्लेटफॉर्म्स को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया।

टिकटॉक की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच, अमेरिकी कंपनियों पर केंद्रित इस प्रस्ताव को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहस तेज हो गई है। बावजूद इसके, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने साफ किया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही फैसले लेगी।

- डिजिटल कंपनियों पर 2.25% टैक्स का प्रस्ताव
- पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को आर्थिक सहयोग लक्ष्य
- 2 जुलाई तक संसद में पेश हो सकता है विधेयक
- समझौता करने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट
- सालाना 200-250 मिलियन डॉलर जुटाने का अनुमान
- 2021 के कानून के बाद दूसरा बड़ा प्रयास
- मेटा और गूगल ने प्रस्ताव का किया विरोध

लोकतंत्र बनाम डिजिटल मुनाफा

सरकार का मानना है कि मजबूत पत्रकारिता लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है, जबकि डिजिटल कंपनियां इसे महज कंटेंट मानती हैं। यह टकराव भविष्य की मीडिया नीति तय करेगा।

वैश्विक असर की संभावना

यदि यह मॉडल सफल होता है, तो अन्य देश भी डिजिटल कंपनियों पर इसी तरह के टैक्स लागू कर सकते हैं, जिससे वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है।

टेक कंपनियों की चिंता

कंपनियों का तर्क है कि यह टैक्स जबरन राजस्व हस्तांतरण है, जिससे उनका बिजनेस मॉडल प्रभावित होगा और वे न्यूज कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटा सकती हैं।

महंगाई और ईरान युद्ध से जनता नाराज, चुनावी समीकरण बदलने के संकेत

ट्रंप की साख पर संकट, अप्रूवल रेटिंग ऐतिहासिक गिरावट पर

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ताजा सर्वे के मुताबिक उनकी अप्रूवल रेटिंग घटकर 34त्न पर पहुंच गई है, जो उनके मौजूदा कार्यकाल का अब तक का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। जनवरी 2025 में सत्ता संभालने के बाद से यह ग्राफ लगातार नीचे की ओर गया है, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण बढ़ती महंगाई और ईरान के साथ जारी युद्ध है। तेल आपूर्ति पर असर पड़ने से पेट्रोल की कीमतों में 40त्न से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे आम अमेरिकी नागरिकों की जेब पर सीधा बोझ पड़ा है। सर्वे में केवल 22त्न लोगों ने महंगाई से निपटने के सरकार के प्रयासों को संतोषजनक बताया, जबकि अधिकांश जनता इससे असंतुष्ट नजर आई।

वहीं, ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर भी जनता में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। सर्वे के मुताबिक, केवल 34त्न अमेरिकी इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग इसके खिलाफ हैं। लगातार बढ़ते सैन्य खर्च और जान-माल के नुकसान की आशंका ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है।

हालांकि रिपब्लिकन पार्टी के पारंपरिक समर्थकों का लगभग 78त्न समर्थन अभी भी ट्रंप के साथ बना हुआ है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर असंतोष की झलक यहां भी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर, डेमोक्रेटिक पार्टी को स्वतंत्र मतदाताओं के बीच बढ़त मिलती नजर आ रही है, जो आगामी चुनावों के लिहाज से अहम संकेत है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर महंगाई और युद्ध जैसे मुद्दों पर सरकार जल्द ठोस कदम नहीं उठाती, तो यह गिरावट चुनावी नतीजों पर गहरा असर डाल सकती है। आने वाले महीनों में ट्रंप प्रशासन के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है कि वह जनता का भरोसा दोबारा कैसे हासिल करे।

महंगाई बना सबसे बड़ा संकट

अमेरिका में बढ़ती महंगाई ने आम जनता की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। पेट्रोल और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि से लोगों में असंतोष तेजी से बढ़ा है। यह मुद्दा ट्रंप की गिरती लोकप्रियता का मुख्य कारण बनकर उभरा है।

चुनावी असर के संकेत

गिरती अप्रूवल रेटिंग का सीधा असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है। स्वतंत्र मतदाताओं का झुकाव डेमोक्रेट्स की ओर बढ़ना ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है, जो भविष्य की राजनीतिक रणनीति को प्रभावित करेगा।

युद्ध पर जनता का बदलता रुख

ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर शुरू में जो समर्थन था, वह अब घटता दिख रहा है। लंबे समय तक चलने वाले युद्ध और इसके आर्थिक प्रभाव ने जनता को इससे दूर कर दिया है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर-208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86739 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com